

Name of the College: APSH College Baranasi  
 Name: Dr. Rajesh Kumar Suran  
 Dept: Economics Date: 18.11.2022  
 Designation: [H/T] units: 02  
 Class: B.A Part-1 [H]  
 Paper: 2nd  
 Name of the topic: Reforms in the Indian tax structure

⇒ पूंजी लाभ कर [Capital gains tax] - कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति एवं प्रतिभूति जैसे भूमि, भवन, शेयर, डिबेंच या कोई अन्य संपत्ति जब अपनी क्रय लागत या निर्माण लागत से अधिक मूल्य बिक्री है तो इस पर होने वाले लाभ ही पूंजी लाभ कहा जाता है। इस पूंजी लाभ पर लगाने वाले कर को ही 'पूंजी लाभ कर' कहते हैं। पूंजी लाभ कर सम्प्रदायिक है आमतौर पर सामान्यतया वार्षिक है।

- (i) अल्पकालीन पूंजी लाभ कर [Short term Capital Gains tax]
- (ii) दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर [Long term Capital Gains tax]
- (i) अल्पकालीन पूंजी लाभ कर :- यदि कोई वित्तीय परिसंपत्ति (जैसे भूमि, भवन इत्यादि) बिक्री के लिए 36 माह (प्रतिभूति जैसे शेयर 1 वर्ष) से कम सम्प्रदायिक है तो इसे रहीं ही है, तो इस प्रतिभूति के बिक्रय से होने वाले पूंजी लाभ पर कर है 'अल्पकालीन पूंजी लाभ कर' कहते हैं।
- (ii) दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर :- यदि कोई वित्तीय परिसंपत्ति (जैसे भूमि, भवन 36 माह से अधिक) या प्रतिभूति (जैसे शेयर 1 वर्ष से अधिक) बिक्री के लिए रहीं ही है, तो इस प्रतिभूति के बिक्रय से होने वाले पूंजी लाभ पर कर है 'दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर' कहते हैं।

⇒ प्रतिभूति विनियमन कर :- प्रतिभूति विनियमन कर एक ऐसा विनियमन कर है जो धरेखू स्टॉक एक्सचेंज में हुए खन-देन पर लगाया जाता है।

प्रतिभूति विनिमय का ही शून्यता 100% 2004 की ही रही।  
 प्रतिभूति विनिमय का ही दरें केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित  
 की जाती हैं। एवं यह एक व्यापक दरसमर्थन की वस्तु सा जाता,  
 है। प्रतिभूति विनिमय का ही वस्तु ही विभिन्न प्रतिभूतियों  
 जैसे:- सीमा, डिबेंच, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड  
 इत्यादि के खरीदने एवं बेचने पर की जाती है।

⇒ अप्रत्यक्ष कर: [Indirect tax] - ऐसे करों को  
 अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिनका भौतिक भार दूसरों पर  
 डाला जाता है अर्थात् अप्रत्यक्ष कर की वित्तीय प्रभाव  
 [Incidence of tax] किसी अन्य व्यक्ति पर होता है  
 और उत्पाद [Impact of tax] किसी अन्य व्यक्ति पर  
 पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर को वित्तीय प्रभाव का वास्तविक  
 भार उक्त व्यक्ति पर नहीं पड़ता, जो उसे अदा करता है।  
 उदाहरण:- उत्पादन कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन  
 कर, बिजली कर, व्यापक शुल्क इत्यादि।

⇒ सीमा शुल्क [Custom Duty] - सेवा का एक अप्रत्यक्ष कर  
 है। जो किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के  
 खर्च में लगाया जाता है और इस कर का भुगतान  
 करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। यह  
 एक केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित एवं वसूल किया जाता  
 है, परंतु विश्व आयोग की सिफारिश पर इसे केन्द्र एवं  
 राज्यों में बांटा जाता है। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा  
 शुल्क बोर्ड सेवा का लगाने एवं वसूलने संबंधित  
 नीति तैयार करता है।

3) उत्पाद शुल्क :- किसी वस्तु का उत्पादन देश के भीतर करने पर केंद्र सरकार द्वारा जोका लगाया जाता है उसे 'उत्पाद शुल्क' कहते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। किंतु शराब, तंबाकू, गोंजा जैसी मादक वस्तुएँ, जो मानवीय उपभोग में आती हैं, के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। यह राज्य सरकारों के लिए राज्य राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसी वस्तुओं पर केंद्र सरकार का नहीं लगाती। तंबाकू के निर्मित वस्तुओं (जैसे - सिगरेट) पर केंद्र सरकार का लगाती है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व का विभाजन विज्ञान आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों द्वारा भारत सरकार के राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है।